आई.सी.यू और डायलेसिस के नाम पर पीपीपी अव्यवस्था

ईएसआई मेडिकल कॉलेज अस्पताल से दिलाया जा रहा मज़दूरों को धोखा

इस कारनामे पर अपनी पीठ थपथपाने जल्द आ रहे प्रधानमंत्री मोदी

फ़रीदाबाद (म.मो.) अस्पताल के विशेषज्ञ डाक्टरों के विरोध के बावजूद निगम मुख्यालय पीपीपी मोड़ में अव्यवस्थित रूप से दिखावटी आईसीयू व डायलेसिस सेवायें चलाता जा रहा है। करीब दो तीन माह पूर्व डीजी ने इस अस्पताल के दौरे के समय इस पाखंड को समाप्त करने का निर्देश दिया था, जिसकी अवज्ञा स्वयं उनका मुख्यालय कर रहा है। एनएच-3 स्थित ईएसआई मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मज़दूरों को धोखा देने के लिये 30 बेड का एक नकली आईसीयू (गहन देख-भाल इकाई) तथा 10 बेड का ऐसा ही नकली एक डायलेसिस विभाग खोल रखा है। औद्योगिक मज़दूरों के वेतन से साढे 6 प्रतिशत झपट कर अपने खजाने में 75000 करोड़ से अधिक जमा कर बैठे इएसआई निगम ने उक्त दोनों सेवाओं की ड्रामेबाज़ी केवल इसलिये शुरू की हुई है ताकि उसे अपने मरीज़ों को व्यापारिक अस्पतालों में रैफ़र न करना पड़े और करोड़ों के रैफ़रल बिल बचाये जा सकें। व्यापारिक अस्पतालों को अदा किये जाने वाले मोटे रैफ़रल बिलों को बंद करना तो अच्छी बात है लेकिन मरीज़ों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करके रोकना बहुत ही बुरी बात है, बल्कि आपराधिक षड्यंत्र है।

पिछले करीब डेढ साल से यहां 30 बेड का आईसीयू चलाने का ड्रामा पीपीपी मोड में किया जा रहा है। इस मोड का मकसद ही होता है पैसा पब्लिक का और मुनाफ़ा प्राइवेट पार्टी का। मज़दूरों के खरबों रुपये पर कुंडली मारे बैठे ईएसआई निगम ने इस यूनिट को खुद चलाने के बजाय 'शील' नामक एक कम्पनी को ठेके पर दे दिया है। यदि ठेकेदार तयशुदा नियमों के अनुसार आईसीयू को चलाये तो उसे मुनाफ़ तो क्या घर से और देना पड़ जायेगा। नियमानुसार 30 बेड के लिये ही शिफ़्ट में 30 स्टाफ़ नर्स के हिसाब से 90 तथा 30 अतिरिक्त यानी कुल 120 स्टाफ़ नर्स तथा विशेषज्ञ डॉक्टरों को रखना पड़ता है। अपने मुनाफ़े के लिये ठेकेदार ने कुल 30 ही नर्सों को रखा है। जाहिर है ऐसे में किसी मरीज़ की सघन देख-भाल तो संभव नहीं, हां देख-भाल का ड्रामा ज़रूर हो सकता है।

बड़ी हैरानी की बात है कि हज़ारों करोड़ लगा कर मेडिकल कॉलेज एवं 500 बेड का अस्पताल तो बना दिया, उसे चलाने एवं रख-रखाव पर करोड़ों रुपये मासिक खर्च भी किया जा रहा है, लेकिन आईसीयू जेसा महत्वपूर्ण काम एक ठेकेदार को दे दिया। क्यों? क्योंकि निगम के मुताबिक यह सस्ता पड़ता है। जाहिर है सस्ता तो तभी पड़ सकता है जब ठेकेदार तय मानकों के मुताबिक सेवायें न देकर खर्च बचाये। क्या निगम के अंधे अधिकारियों को यह दिखाई नहीं देता? क्या निगम में बैठे उच्चाधिकारी इतने बेवकूफ़ हैं जो इतनी छोटी सी बात को भी नहीं समझ पा रहे?

राजकुमार (डीजी) ईएसआईसी: सही निर्देश लेकिन दिशाहीन मुख्यालय

इस से भी बुरा हाल डायलेसिस यूनिट का है। इस शहर में ईएसआई कवर्ड 800 मरीज़ ऐसे हैं जिनकी किडनी ठीक से काम नहीं करती। खून से यूरिया आदि साफ़ कराने के लिये सप्ताह में कम से कम 2 बार डायलेसिस कराना पड़ता है। इसके लिये निगम अपने मरीज़ों को व्यापारिक अस्पतालों को रैफ़र करता था। इसके लिये इन अस्पतालों से एक रेट कॉन्ट्रेक्ट किया जाता है। व्यापारिक अस्पतालों की नीयत रहती है कि यदि बेड खाली है तो इन 'रेट कॉन्ट्रेक्ट' वाले मरीज़ों का डायलेसिस कर दो अन्यथा टरका दो। उधर ठेकेदार कम्पनी ने ईएसआई निगम को उक्त रेट कॉन्ट्रेक्ट से भी आधे दामों पर डायलेसिस करने का प्रस्ताव दे दिया। बस फ़िर क्या था, अक्ल के अंधे और गांठ के पूरे निगम अफ़सरों ने झट से इस ऑफ़र को लपक लिया और कुल 10 बेड का डायलेसिस यूनिट चालू कर दिया। इस से केवल 80 मरीज़ों को ही डायलेसिस संभव है। शेष 720 को अब भी रैफ़र करना पड़ता है।

अब सोचने वाली बात यह है कि जिस रेट कॉन्ट्रेक्ट पर व्यापारिक अस्पताल डायलेसिस करने से कतराते हैं तो यह ठेकेदार उस से भी आधे रेट पर कैसे डायलेसिस कर देगा? लेकिन चोरों की सरकार में बैठे धूर्त अफ़सरों को यह सोचने समझने की जरूरत ही क्या है? उन्होंने कौन सा अपना इलाज कराना है यहां। लेकिन **'मज़दूर मोर्चा'** को यह रहस्य खोजने की जरूरत महसूस हुई और उसे खोजा भी।

सर्वप्रथम डायलेसिस प्रक्रिया के दौरान एक किडनी विशेषज्ञ डॉक्टर तथा एक मेडिसिन विशेषज्ञ का उपस्थित रहना आवश्यक है। जो दोनों ही इस ठेकेदार के पास नहीं हैं। केवल 2-3 टेक्नीशियन रखे हुए हैं जो मरीज को मशीन से जोड़ कर प्रक्रिया चालू कर देते हैं।

दूसरा यह है कि प्रक्रिया में एक तरल रसायन डायलायजर मरीज़ के शरीर में चढाया जाता है जो सारे शरीर में घूम कर रक्त में मौजूद यूरिया (पेशाब) आदि को लेकर वापस आता है जिससे रक्त 2-3 दिन के लिये साफ़ हो जाता है। नियमानुसार यह कीमती तरल रसायन 3 बार से अधिक बार प्रयोग नहीं किया जा सकता, परन्तु खर्च बचाकर मुनाफ़ा कमाने के लिये ठेकेदार इस रसायन को 9 से 10 बार तक इस्तेमाल करके मरीज़ों के जीवन से खिलवाड़ करता है।

ठेकेदार की इस बेइमानी एवं धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप मरीज़ों को संक्रमण होने के साथ-साथ सांस लेने में दिक्कत तथा सिर दर्द आदि की शिकायत हो जाती है लेकिन कोई सुनता नहीं। हां यदि 100-200 लोग हंगामा करें तो मरीज़ को किसी व्यापारिक अस्पताल को रेफ़र कर दिया जाता है।

डबुआ कॉलोनी निवासी 28 वर्षीय दीपक इतना भाग्यशाली नहीं था। करीब 30-35 बार यहां के डायलेसिस ने उसकी बीमारी को इतना बढा दिया कि 10 मार्च को उसने प्राण त्याग दिये।

मज़दूरों के साथ किये जा रहे इस खिलवाड़ पर अपनी पीठ थपथपाने को प्रधानमंत्री मोदी भी मई के अन्तिम सप्ताह में यहां पधारने वाले हैं। यहां आकर वे लम्बी-लम्बी छोड़ेंगे। दुनिया भर का झूठ बिखेरेंगे, भाड़े के भांड तालियां बजायेंगे और मोदी-मोदी चिल्लायेंगे।

मुजेसर गांव की डिस्पेंसरी गेट पर पेड़ के नीचे प्रसव : सरकारी हरामखोरी का एक नमूना

फ़रीदाबाद (म.मो.) गत सप्ताह एसी नगर की एक गर्भवती महिला को प्रात: 4 बजे प्रसव पीड़ा हुई तो परिजन उसे सरकारी झांसे में आकर मुजेसर गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर (पीएचसी) एवं जच्चा-बच्चा केन्द्र पहुंच गये। उन्हें, दरअसल सरकार की इस बात पर भरोसा था कि यह रात-दिन, चौबीसों घंटे प्रसव सम्बन्धी सेवायें देता है।

इस ग़रीब परिवार का सरकार के प्रति भरोसा उस वक्त चूर-चूर हो गया जब उन्हें वहां ताला लगा मिला। दूसरा दरवाज़ा जो अंदर से बंद था उसको काफ़ी देर तक ये लोग पीटते रहे। लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिला, हां इस बीच प्रसव से कराहती महिला ने वहीं एक पेड़ के नीचे जैसे-तैसे एक बच्चे को जन्म दे दिया।

कुछ देर बाद शोर-शराबा सुन कर तथा भोर का हल्का उजाला देख कर तिमंजले पर अपने क्वार्टर में सोई नर्स की आंख खुली तो उसने झटपट आकर मामले को सम्भालने का प्रयास करते हुये महिला एवं शिशु को बेड पर लिटाया। बेड पर बिछी चादर इतनी गंदी थी कि बिना मजबूरी के कोई उस पर बैठने तक को राज़ी न हो। चादर गंदी इस लिये थी कि इसे धोने व सफ़ाई की कोई व्यवस्था यहां नहीं है।

असल में जिस नर्स ने सोते से उठ कर इस केस को सम्भाला, उसकी उस वक्त ड्यूटी नहीं थी और जिसकी ड्यूटी थी वह ताला लगा कर अपने घर चली गयी थी। यहां की डॉक्टर नीरू गुप्ता के रहने की आसपास कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है इसलिये वे अपने घर पर रहती हैं, जरूरत पड़ने पर ड्यूटी नर्स कॉल करके उन्हें बुला लेने का प्रावधान है। जबकि नियमानुसार डॉक्टर को इसी परिसर में यथोचित आवास प्रदान किया जाना चाहिये।

चलताऊ एवं दिखावटी काम करने में निपुण सरकार ने डॉक्टर तथा नर्सों को स्थाई नौकरी पर रखने की अपेक्षा ठेकेदारी में रखा हुआ है ताकि खर्चा बचाया जा सके। विदित है कि ठेकेदारी में कच्ची नौकरी करने वालों की न तो कोई ज़िम्मेदारी होती है और न ही उन्हें ऐसी नौकरी छूटने का कोई खास डर होता है।

डॉ. नीरू गुप्ता व नर्सों को नौकरी से हटा कर अपनी पीठ थपथपाने वाली सरकार यदि यहां के सीएमओ गुलशन अरोड़ा एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्यवाही करती तो ऐसे शेष सेंटरों की कार्यशैली में कुछ सुधार हो सकता था। उक्त घटना से करीब 3 माह पहले **'मज़दूर मोर्चा' के 16-31 जनवरी 2018** के अंक में इसी सेंटर की दुर्दशा एवं किसी संभावित दुर्घटना के बाबत विस्तृत विवरण प्रकाशित किया था लेकिन उसे पढने के बावजूद सीएमओ सहित किसी अधिकारी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी।

विधायक सीमा के प्रयासों के बावजूद फ्लॉप रहा खट्टर का गढ्ढर

फ़रीदाबाद (म.मो.) 28 अप्रैल बड़खल विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के रोड शो के लिये विधायक सीमा त्रिखा ने एड़ी-चोटी का जोर लगाकर पूरे क्षेत्र के मंदिरों, पार्कों, मोहल्लों, कॉलोनियों में जा-जा कर अपनी झोली फ़ैलाई व मीटिंगे रखवाई। त्रिखा ने उन सभी लोगों को फ़ोन भी किये जिन्होंने चुनाव के दौरान त्रिखा के बूथ व झोले संभाले थे।

त्रिखा के रिश्तेदारों, इनके द्वारा बनाए प्रधानों हारे-जीते पार्षदों ने, कई दिनों तक खूब जोर लगाया। बावजूद इसके पूरे क्षेत्र से रोड शो के दौरान 500-700 आदमी भी नहीं जुटा पाये। जिसको लेकर पूरे बडखल क्षेत्र में चर्चा रही कि विधायक सीमा त्रिखा ने समय रहते अगर पंजाबी बिरादरी व समाज के किसी भी व्यक्ति का भला किया होता तो आज ये दुर्गति न होती।

मुख्यमंत्री के रोड शो के दौरान शहर की मेयर को लोगों ने पैदल धक्के खाते देखा, वहीं दूसरी तरफ़ शहर के अपराधियों को संरक्षण देने वाले व पुलिस के नाम पर थाने-चौकियों में दलाली करने वाले शराब ठेकेदार तनेंद्र टंडन को विधायक पति अश्वनी त्रिखा ने अपने साथ खुली जीप में बाकायदा कुर्सी लगाकर बैठा रखा था। वहीं मुख्यमंत्री के रोड शो में एन.एच. 5 में शहर के ऑनलाईन कैसिनो संचालकों, भू-माफ़ियाओं, अवैध बिल्डरों व प्रोपर्टी डीलरों के तथाकथित प्रधान नरेश चावला ने अपने पूरे गिरोह के साथ बढ-चढ कर हिस्सा लिया व के एल मेहता दयानंद वूमेन कॉलेज के पास तम्बू लगा कर खाने-पीने का पूरा बंदोबस्त भी किया जिसमें सारे शहर के उठाईगिरे मौजूद थे। जिसका उदाहरण रोड शो में उस वक्त देखने को मिला जब इसी तम्बू में ही नरेश चावला के साथी बिल्डरों की जेब कटी व मोबाईल फ़ोन भी चोरी हो गये।

मुख्यमंत्री के रोड शो के दौरान बांके बिहारी मंदिर में फिर से चोरों ने स्टार हॉस्पिटल जो कि मंदिर परिसर में ही बना हुआ है, से बाइक चोरी कर पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह भी लगा दिया।

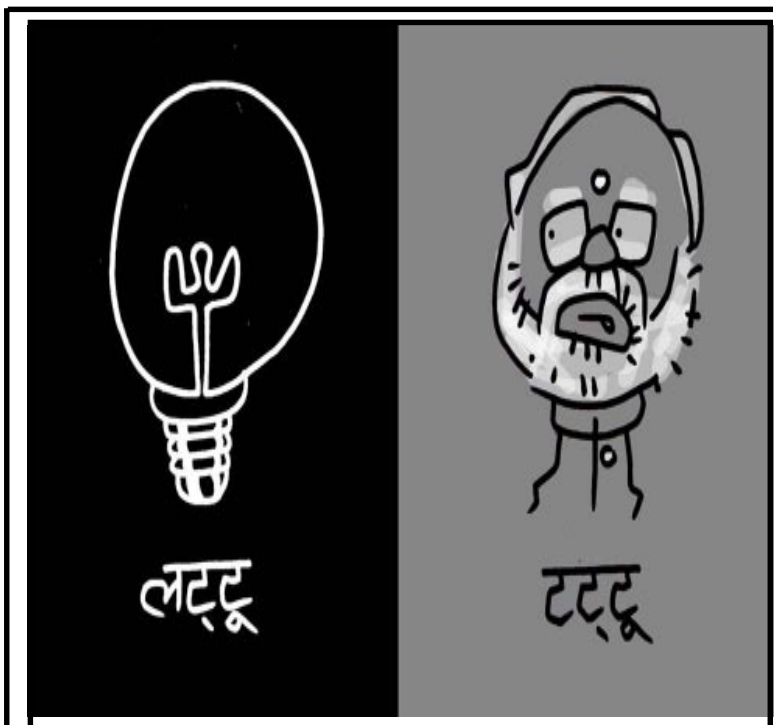

दावा, गांव-गांव में बिजली का लट्टू यानी झूठ का सरपट दौड़ता मोदी का टट्टू!

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06